Common Economic Zone for the National Capital Region

1045. SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA:
SHRI AKHILESH DAS:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to establish a Common Economic Zone for the National Capital Region; and

(b) if so, the details thereof indicating the precise objectives, parameters and cost?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVANOOR): (a) and (b) To promote the NCR one of the strategies is to consider the setting up of a Common Economic Zone comprising of Delhi and parts of Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh. The basic philosophy behind the concept of Common Economic Zone (CEZ) is to evolve a harmonized policy for balance development of the entire region. Broadly this concept would entail developing NCR as a Common Economic Zone with broad features such as common planning approach, uniform fiscal policy, uniform level of integrated physical infrastructure and financial allocation and resource generation treating CEZ as a single entity. To achieve this objective it was desired that the Chief Ministers of the concerned States may hold a conference to consider these issues.

राज्य सरकारों द्वारा धनराशि का उपयोग

1046. **श्री राम जेठमलानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विभिन्न योजनाओं के तहत व्यय की गई वास्तविक राशि का सही-सही आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो वह राशि कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा आठवीं योजना के अंतर्गत व्यय करने हेतु कुल कितनी राशि आवंटित की गई थी तथा इसमें योजनागत व्यय तथा गैर-योजना गत व्यय के अंतर्गत प्रदान की गई अलग-अलग राशि कितनी-कितनी थी;

(घ) क्या यह सच है कि देश के अनेक राज्य ऐसे भी हैं जहां योजनागत व्यय के अंतर्गत आवंटित राशि से 50 प्रतिशत से भी कम व्यय किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विभिन्न योजनाओं के तहत व्यय की गई राशि का सही-सही आंकलन नहीं किया गया है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को (1991-92) की कीमतों पर 434100 करोड़ रु० के परिव्यय के आधार पर बनाया गया था। आठवीं योजना व्यय 391000 करोड़ रु० था। केन्द्र और राज्यों के लिए गैर-योजना व्यय के अंतर्गत खर्च के लिए आवंटित राशि को एकत्रित किया जा रहा है। तथापि, आरबीआई वार्षिक प्रकाशन "फाइनन्सेज आफ स्टेट गवर्नमेंट" में तथा भारत सरकार के व्यय बजट में दी गई जानकारी के अनुसार आठवीं योजना आवधि (1992-93 से 1996-97) के वास्ते (केन्द्र और राज्य दोनों के लिए) कुल गैर-योजना व्यय का आंकलन (वर्तमान कीमतों पर 1144442 करोड़ रु० हैं)।

(घ) और (ङ) प्रत्याशित योजना व्यय बिहार के लिए आठवीं योजना परिव्यय के लिए अनुमोदित राशि से 50 प्रतिशत से भी कम था।

Implementation of recommendations of the High Level Committee on North East States

1047. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the recommendations of the High Level Committee on North-Eastern States announced by the former Prime Minister, Shri H. D. Devegowda;

(b) the steps taken to implement the recommendations; and

(c) whether Government are sure that the present arrangement will satisfy the people of North East?